भारत सरकार

योजना मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4340

दिनांक 26.03.2025 को उत्तर देने के लिए

नीति आयोग रिपोर्ट 2014-15

4340. **श्री धर्मेन्द्र यादव:**

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नीति आयोग की रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग की 70 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कई सीटें योग्य उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण खाली रह गईं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नीति आयोग की रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार सार्वजनिक सेवा में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कई रिक्तियां पर्याप्त शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण खाली रह गईं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नीति आयोग की रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग की शैक्षिक स्थिति मुख्यधारा के समुदायों से बेहतर नहीं है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार की अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति उप-योजना की तर्ज पर एक विशेष कार्य-योजना बनाने की योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो यह कब तक पूरा होने की संभावना है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं

राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) और (ग) उद्धृत रिपोर्ट में दिया गया विवरण 10 वर्ष पहले की अवधि से संबंधित है। उच्च शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के नामांकन में काफी सुधार हुआ है। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, ओबीसी के नामांकन में लगातार वृद्धि हुई है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

वर्ष	2016-17	2018-19	2020-21	2021-22
ओबीसी नामांकन	1,22,99,309	1,35,91,994	1,48,21,537	1,63,36,460

(ख) उद्धृत रिपोर्ट में दिया गया विवरण 10 साल पहले की अवधि से संबंधित है। बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों सहित रिक्तियों का होना और भरना एक सतत प्रक्रिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों की पहचान के लिए एक इन-हाउस समिति गठित करने के अनुदेश जारी किए गए हैं ताकि ऐसी रिक्तियों के मूल कारण का अध्ययन किया जा सके, ऐसी रिक्तियों का कारण बनने वाले कारकों को दूर करने के उपाय शुरू किए जा सकें और विशेष भर्ती अभियान सहित उन्हें भरा जा सके। मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 2016 से 4 लाख से अधिक बैकलॉग आरक्षित रिक्तियां भरी गई हैं, जिनमें ओबीसी की 1.55 लाख बैकलॉग आरक्षित रिक्तियां शामिल हैं। इसके अलावा, सरकार द्वारा की जाने वाली सीधी भर्ती में ओबीसी का प्रतिनिधित्व भी पिछले 10 वर्षों के दौरान लगातार 27% से अधिक रहा है।

(घ) एवं (ङ) कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालाँकि, सरकार ने निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से ओबीसी समुदाय के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई पहल की हैं:

(i) केंद्र सरकार की नौकरियों में सीधी भर्ती और केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के मामले में ओबीसी को 27% आरक्षण उपलब्ध है।
(ii) कक्षा I से X तक के छात्रों के लिए- ओबीसी के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति।
(iii) कक्षा XI और XII के छात्रों के लिए- ओबीसी छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति।
(iv) युवा उपलब्धि योजना (श्रेयस) (ओबीसी और अन्य) के लिए उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति
(v) वाइब्रेंट इंडिया के लिए पीएम यंग अचीवर्स छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना (पीएम-यशस्वी)
(vi) ओबीसी के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप
(vii) ओबीसी लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावासों का निर्माण
(viii) ओबीसी/डीएनटी/ईबीसी के कौशल विकास के लिए सहायता
(ix) ओबीसी के लिए वेंचर कैपिटल फंड की शुरूआत।
(x) ओबीसी के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) की निम्न ब्याज ऋण/वित्त सहायता योजनाएं।

उपर्युक्त योजनाओं के अलावा, सरकार कई योजनाएं लागू कर रही है जहां योजनाओं को पूरा करने वाले दृष्टिकोण को अपनाया गया है, जिससे भी ओबीसी समुदायों को लाभ होता है। इनमें हर घर जल योजना, पीएम आवास योजना, मिशन इंद्रधनुष, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम जन आरोग्य योजना, पीएम स्वनिधि, पीएम मातृ वंदना योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम मुद्रा योजना, पीएम पोषण योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना आदि शामिल है।

*****